5 Protection of forests through Implementation of the Indian Forest Act, 1927 and the Forest (Conservation)Act 1980, development of non-conventional energy sources and schemes for substitution of wood.

6 Afforestation Programmes.

7 Preservation of critical eco-systems and protection of wildlife through 69 National Park and 397 Sanctuaries and through implementation of the Wildlife (Protection) Act, 1972.

8 Action programmes for marine eco-systems, wetlands and mangroves.

9 Formulation of policy and strengthening of legislaton for environment and forestry.

10 Promotion of research, education, and training in environmental and forestry subjects.

11 Creation of environmental awareness.

Amendments in CSIR Administrative Service (Recruitment & Promotion Rules) 1982

62. SHRI BEKAL UTSAHI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several amendments have been made in the CSIR Administrative Service (Recruitment and Promotion) Rules, 1982 during the last two years to the detriment of one group of officers and leading to demoralisation in the organisation;

(b) if so, what are the details in this regard;

(c) whether it is a fact that the Governing Body of CSIR was misled in obtaining one time relaxation in filling Departmental examination quota posts in the grade of Deputy Purchase Officer by promotion from within the Department, when there was no stagnation and Departmental Officers were promoted by giving relaxation; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (PROF. M. G. K. MENON): (a) No, Sir. Only two amendments have been made in the CSIR Administrative Services (Recruitment & Promotion) Rules during the last two years. These were not to the detriment of any one group of officers but aimed at equitable promotional opportunities.

(b) The details are as follows:—

(i) Recruitment to the grade of Deputy Secretary/Controller of Administration in the grade of Rs. 3700—5000 this was necessitated because of the introduction of new concept of having a single functionary (Controller of Administration) to be in charge of the entire administration in the Laboratory such as Stores & Purchase, Finance & Accounts and General Administration, as recommended by the CSIR Review Committee; and thus to provide promotional opportunities at this level to all these cadres.

(ii) Recruitment Rules pertaining to Stores & Purchase Cadre—this was necessitated because of deletion of two grades of Rs. 2200—4000 and Rs. 1640—2900, as recommended by the High Powered Committee and approved by the Governing Body, CSIR and to remove disparities vis-a-vis other Cadres.

(c) No, Sir. The Governing Body was rightly informed about the stagnation in the garde of Rs. 1400—2000 of Stores & Purchase Cadre.

(d) Does not arise.

Recommendation of the Anomaly Committee on the pay scale of Assistants

63. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Unstarred

Question 2600 given in the Rajya Sabha on the 8th August, 1989 and state:

(a) whether the Anomaly Committee has given its recommendations for the grant of a pay scale of Rs. 1640—2900 to Assistants;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is Government's reaction thereto and by when orders in this regard are likely to be issued?

THE PRIME MINISTER AND THE MINISTER FOR PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

वाराणसी और पटना में गंगा में हो रहे प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाना

64. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा कार्य योजना के अधीन वाराणसी और पटना में गंगा के प्रदूषण पर अब तक किस सीमा तक नियंत्रण किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) गंगा कार्य योजना के अंतर्गत वाराणसी के लिए 39.58 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 35 स्कीमें और पटना के लिए 23.58 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 30 स्कीमें संस्वीकृत की गई हैं। इनमें से अब तक वाराणसी में 16 स्कीमें और पटना में 12 स्कीमें पूरी की जा चुकी हैं। पूरी की गई स्कीमों के परिणामस्वरूप अभी तक वाराणसी में 2.18 करोड़ रुपए लीटर प्रतिदिन और पटना में 3 करोड़ लीटर प्रतिदिन अपशिष्ट जल का अवरोधन दिशा परिवर्तन और उपचार किया जा चुका है। शेष अधिकांश स्कीमों के चालू वित्त वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है। सभी अनुमोदित स्कीमों के पूरा हो जाने पर वाराणसी में गंगा में प्रवाहित होने वाले 10.20 करोड़ लीटर प्रतिदिन तथा पटना में प्रवाहित होने वाले 6.7 करोड़ लीटर प्रतिदिन अपशिष्ट जल के अवरोधन, दिशा-परिवर्तन और उपचार की संभावना है।

दिल्ली चिड़ियाघर की महिला कर्मचारियों द्वारा की गई शिकायतें

65. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली चिड़ियाघर की कुछ महिला कर्मचारियों से वहां के कार्यकारी निदेशक के खिलाफ उनके द्वारा उनसे दुर्व्यवहार करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यालयों में महिला कर्मचारी मान-मर्यादा के साथ अपना कार्य करें, सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली की तीन महिला कर्मचारियों ने कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य करते हुए राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के संयुक्त निदेशक द्वारा किए गए अशोभनीय और अनुचित व्यवहार तथा राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के कुछ कर्मचारियों की अनुशासनहीनता के प्रति ढिलाई दिखाने के संबंध में सरकार को अभ्यावेदन दिए थे। आरोप पर प्राथमिक जांच चल रही है।

सरकार अपने सभी कर्मचारियों को कार्य करने के लिए साफ और स्वस्थ परिवेश मुहैया कराने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि महिला कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर अपने आप को असुरक्षित या तिरस्कृत महसूस न करें।